



SAFALTA CLASSTM

An Initiative by **अमरउजाला**

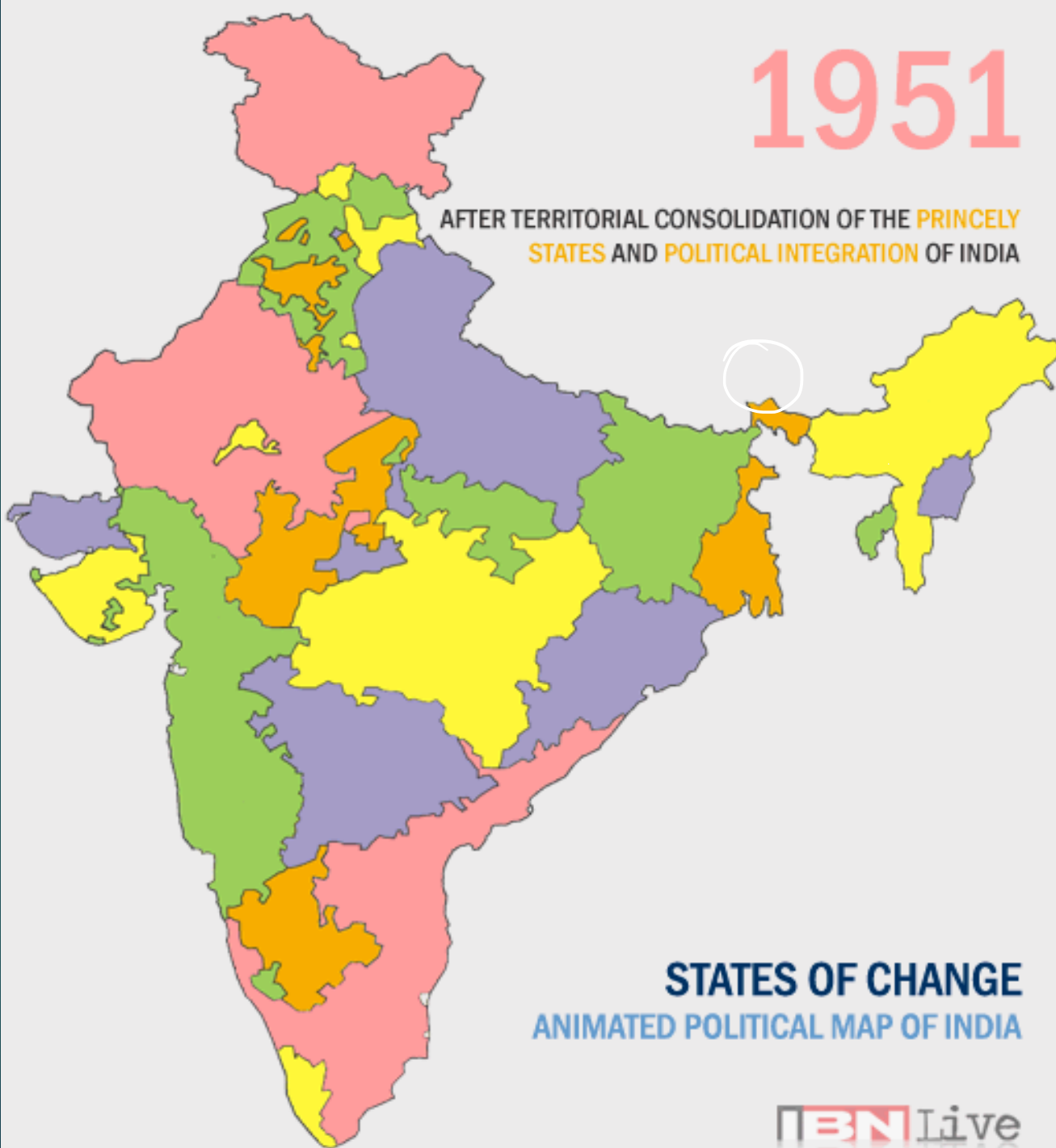
INDIAN POLITY BY- SUJEET BAJPAI SIR





1951

AFTER TERRITORIAL CONSOLIDATION OF THE PRINCELY
STATES AND POLITICAL INTEGRATION OF INDIA



STATES OF CHANGE
ANIMATED POLITICAL MAP OF INDIA

PNB Live

UNION &
IT IS
TERRITORY

1947 ⇒ भाषाई आधार पर

राज्यों की
गिनती

June, 1948 ⇒ हर भाषा

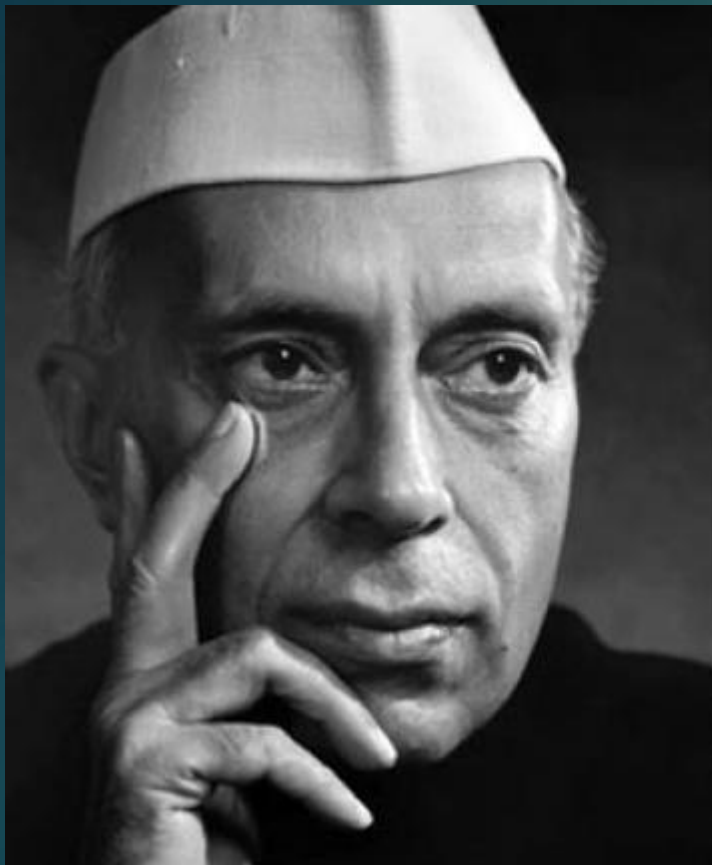
↓

(Report)

S.K. Dhar Comm.
(Ald. H.C. - Judge)

L (Dec. - 1948)

भाषा (X)



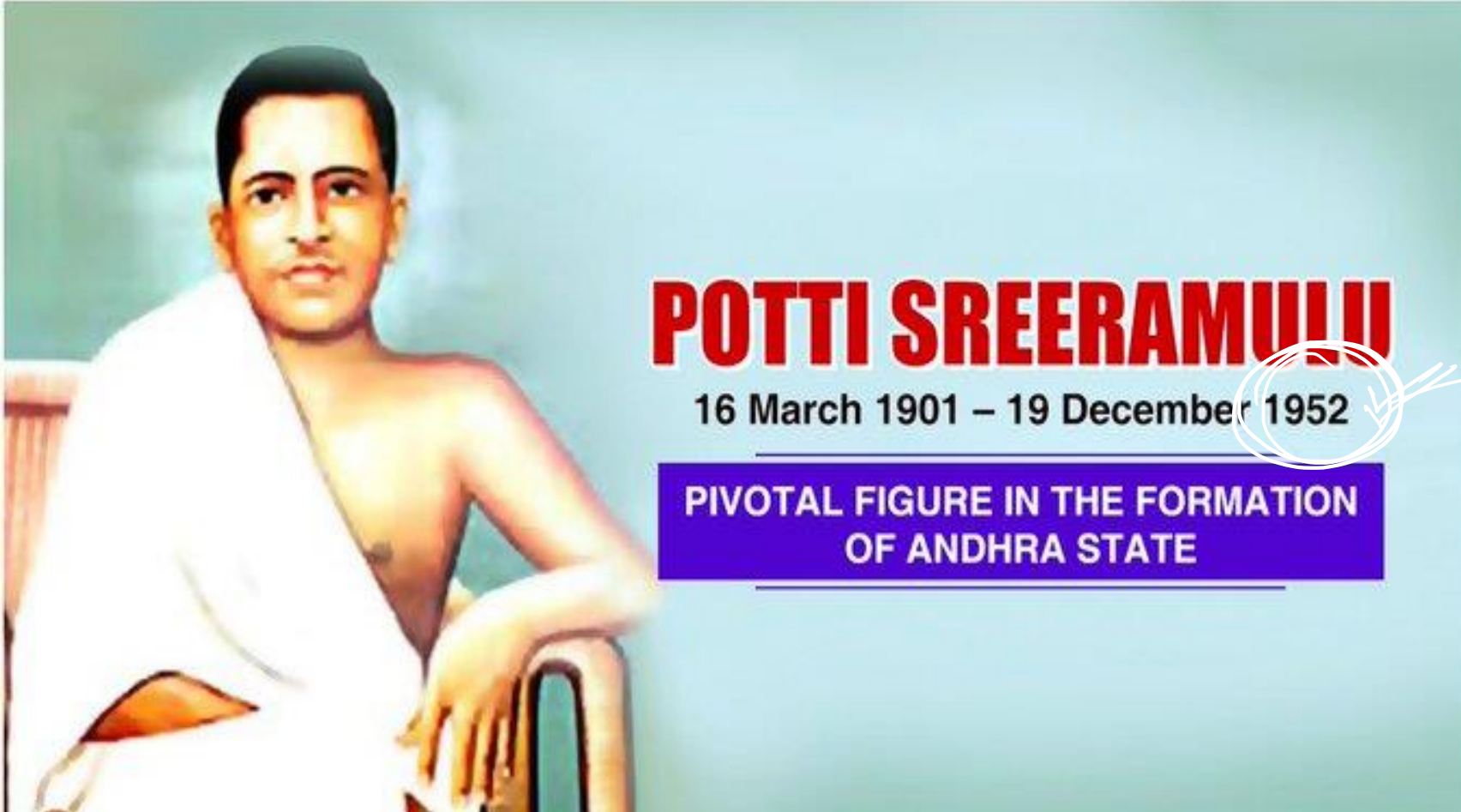
JVP
Comm.
II
Dec.
1948
II
Apr. 8th
1949

15/

भाषा ✓
(X)

P
(पेट्टाकि)

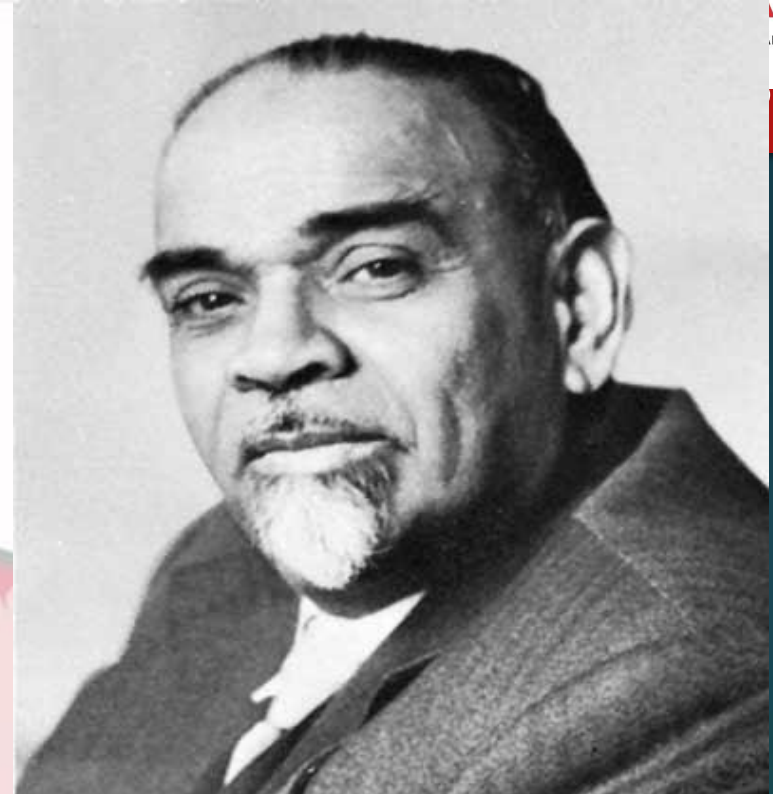
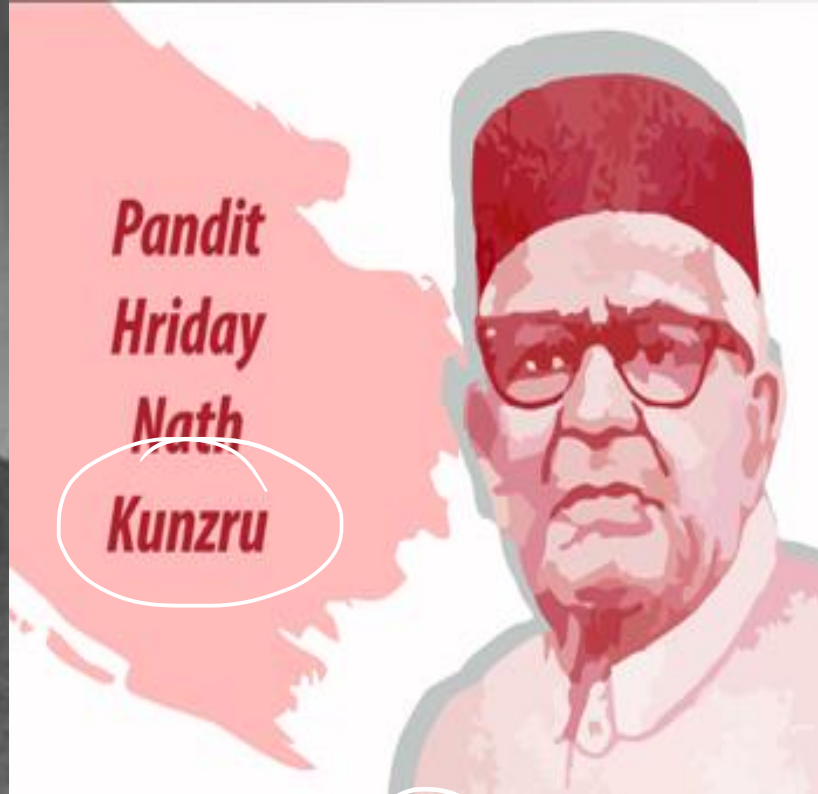
Congress



महात्मा
⇒ पोद्दी
श्री रामुलु
1953
(नेलु)

IN
Andhra

1953 → Andhra Pradesh
[ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ
ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ]
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ



चपल गली 7
①

②
भाषा ✓

③
पुष्पिका

Dhar Commission and JVP Committee:

The integration of princely states with the rest of India has purely an ad hoc arrangement.

There has been a demand from different regions, particularly South India, for reorganisation of states on linguistic basis.

धर आयोग और जेवीपी समिति:

शेष भारत के साथ रियासतों के एकीकरण में विशुद्ध रूप से तदर्थ व्यवस्था है ।

भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर दक्षिण भारत से मांग की गई है।

Accordingly, in June 1948, the Government of India appointed the Linguistic Provinces Commission under the chairmanship of S K Dhar to examine the feasibility of this.

The commission submitted its report in December 1948 and recommended the reorganisation of states on the basis of administrative convenience rather than linguistic factor.

तदनसार, जून 1948 में भारत सरकार ने इसकी व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की।

आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और भाषाई फैक्टर के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की।

This created much resentment and led to the appointment of another Linguistic Provinces Committee by the Congress in December 1948 itself to examine the whole question afresh.

इससे काफी नाराजगी पैदा हुई और दिसंबर 1948 में ही कांग्रेस द्वारा एक और भाषाई प्रांत समिति की नियुक्ति कर इस पूरे सवाल की नए सिरे से जांच की गई।

It consisted of Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Pattabhi Sitaramayya and hence, was popularly known as JVP Committee.

It submitted its report in April 1949 and formally rejected language as the basis for reorganisation of states.

इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभि सीतारामैया शामिल थे और इसलिए उन्हें जेवीपी कमेटी के नाम से जाना जाता था ।

इसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और औपचारिक रूप से भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में अस्वीकार कर दिया ।

However, in October 1953, the Government of India was forced to create the first linguistic state, known as Andhra state, by separating the Telugu speaking areas from the Madras state.

This followed a prolonged popular agitation and the death of Potti Sriramulu (Died: Dec-1952), a Congress person of standing, after a 56-day hunger strike for the cause.

हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र राज्य के नाम से जाना जाने वाला पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

इसके बाद लंबे समय तक लोकप्रिय आंदोलन चला और कांग्रेस के खड़े व्यक्ति पोर्टी श्रीरामुलु की मौत के बाद 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इस कारण से मौत हो गई ।

Fazl Ali Commission

(1953 - 1955)
Report

The creation of Andhra state intensified the demand from other regions for creation of states on linguistic basis.

This forced the Government of India to appoint (in December 1953) a three-member States Reorganisation Commission under the chairmanship of Fazl Ali to re-examine the whole question.

फजल अली आयोग



आंध्र राज्य के निर्माण से भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए अन्य क्षेत्रों से मांग तेज हो गई।

इससे भारत सरकार को (दिसंबर 1953 में) फजल अली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने को मजबूर होना पड़ा और पूरे सवाल की फिर से जांच की गई।

Its other two members were K M Panikkar and H N Kunzru.

It submitted its report in September 1955 and broadly accepted language as the basis of reorganisation of states. But, it rejected the theory of 'one language–one state'.

Its view was that the unity of India should be regarded as the primary consideration in any redrawing of the country's political units.

इसके अन्य दो सदस्य केएम पाणिकर और एच एन कुंजरू थे।

इसने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में मोटे तौर पर भाषा को स्वीकार किया।

लेकिन, इसने 'एक भाषा-एक राज्य' के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसका विचार यह था कि देश की राजनीतिक इकाइयों को फिर से तैयार करने में भारत की एकता को प्राथमिक विचार माना जाना चाहिए।

✓✓
According to Article 1, the territory of India can be classified into three categories:

✓
[NRd ⊕ India]
Acquired Area ⊕ States ⊕ UT

1. Territories of the states
2. Union territories
3. Territories that may be acquired by the Government of India at any time.

Indian Territory

अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारत के क्षेत्र को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. राज्यों के प्रदेशों ✓
2. केंद्र शासित प्रदेश ✓
3. ऐसे क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत किए जा सकते हैं।

Ind. Union

Article 2 grants power to the Parliament:

(A) the power to establish new states.

अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति प्रदान करता है:

(क) नए राज्यों की स्थापना की शक्ति ।

The first refers to the admission of states which are already in existence while the second refers to the establishment of **states which were not in existence before.**

पहला उन राज्यों के प्रवेश को संदर्भित करता है जो पहले से अस्तित्व में हैं जबकि दूसरा उन राज्यों की स्थापना को संदर्भित करता है जो पहले अस्तित्व में नहीं थे ।

Article 3, on the other hand, relates to the formation of or changes in the existing states of the Union of India.

In other words, Article 3 deals with the internal re-adjustment of the territories of the constituent states of the Union of India.

दूसरी ओर अनुच्छेद 3 भारत संघ के मौजूदा राज्यों के गठन या बदलाव से संबंधित है।

दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 3 भारत संघ के घटक राज्यों के क्षेत्रों के आंतरिक समायोजन से संबंधित है ।

Art-4 (Art-2 & 3)

↳ गरीबों Amendment

That will not be
Art-368 [considered As
const Amend

→ Part-3 (+) USA 71 ✓

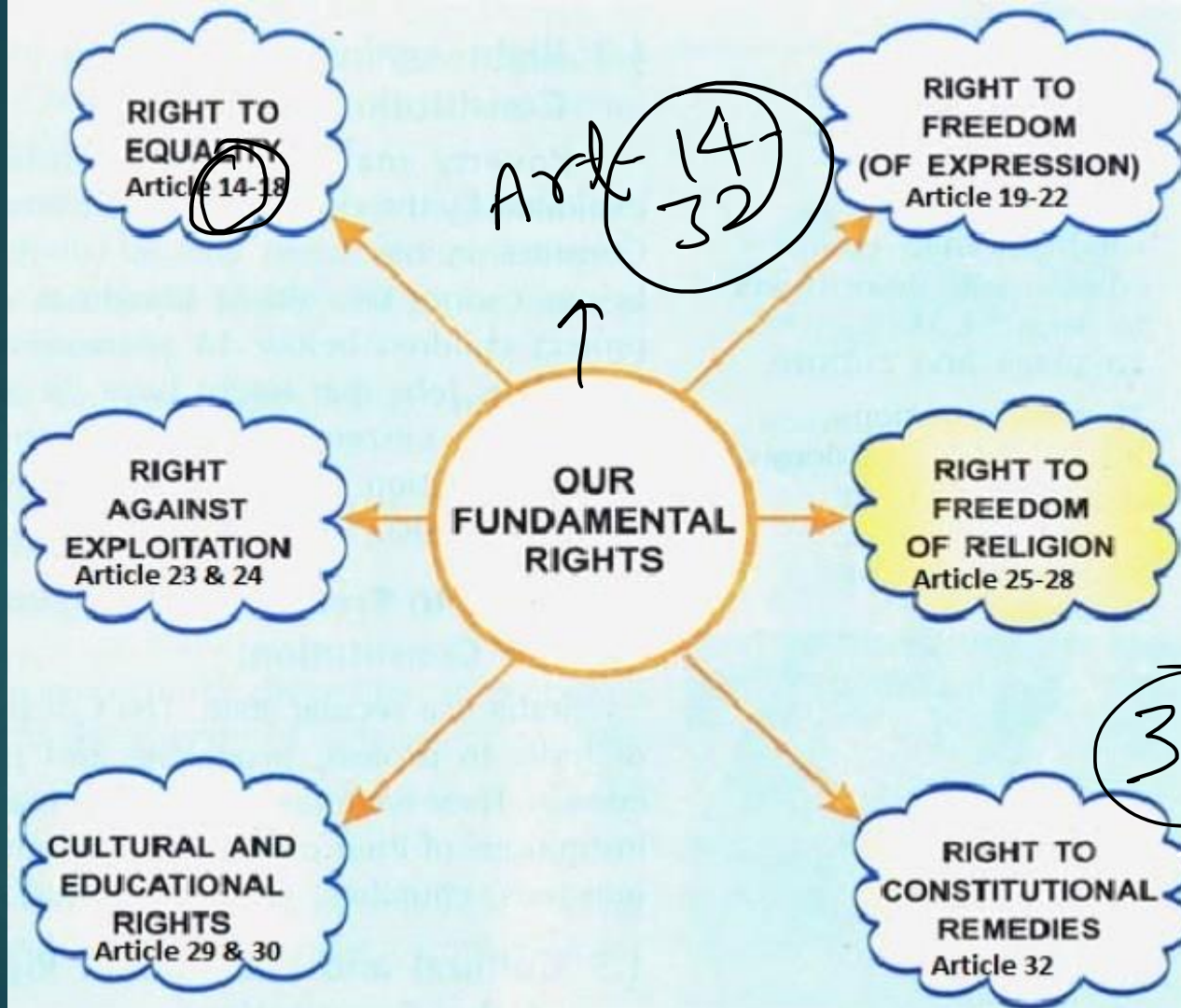
Fundamental Rights



⇒ मूल
Orig →
(7)
⇒ वर्तमान ~
(6)

①

RR (Impo)



②

RR

④

③②

⑥

Ambedkar
Heart &
soul of
every
const.

③

⑤

The Fundamental Rights are enshrined in Part III of the Constitution from Articles 12 to 35.

In this regard, the framers of the Constitution derived inspiration from the Constitution of USA (i.e., Bill of Rights).

मौलिक अधिकार संविधान के भाग-III में अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रतिष्ठापित हैं ।

इस संबंध में संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान (यानी अधिकारों के विधेयक) से प्रेरणा प्राप्त की।

Originally, the Constitution provided for seven Fundamental Rights-

- 1.Right to equality (Articles 14–18)
- 2.Right to freedom (Articles 19–22)
3. Right against exploitation (Articles 23–24)

मूल रूप से संविधान में सात मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था-

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
3. शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

4. Right to freedom of religion (Articles 25–28)
5. Cultural and educational rights (Articles 29–30)
6. [Right to property (Article 31)]
7. Right to constitutional remedies (Article 32)

✓ Legal Rt ⊕ Const. Rt.
Art 300A
अनुवि-12

1978 | 44th
X [Rt. to property]

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
6. संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31)
7. संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)

✓
However, the right to property was deleted from the list of Fundamental Rights by the 44th Amendment Act, 1978.

It is made a legal right under Article 300-A in Part XII of the Constitution. So at present, there are only six Fundamental Rights.

✓
हालांकि, 44 वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था।

इसे संविधान के भाग 12वीं में अनुच्छेद 300-ए के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है। इसलिए वर्तमान में केवल छह मौलिक अधिकार हैं ।

Features of Fundamental Rights:

1. Some of them are available only to the citizens.
2. The state can impose reasonable restrictions on them.

मौलिक अधिकारों की विशेषताएं:

1. उनमें से कुछ केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। eg ⇒ Art-14, 19, 29, 30 etc.
2. राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

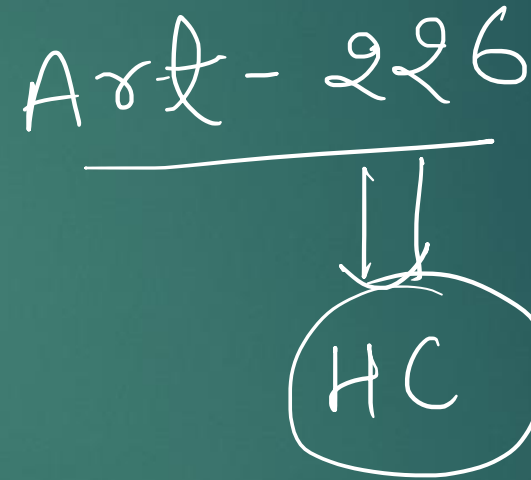
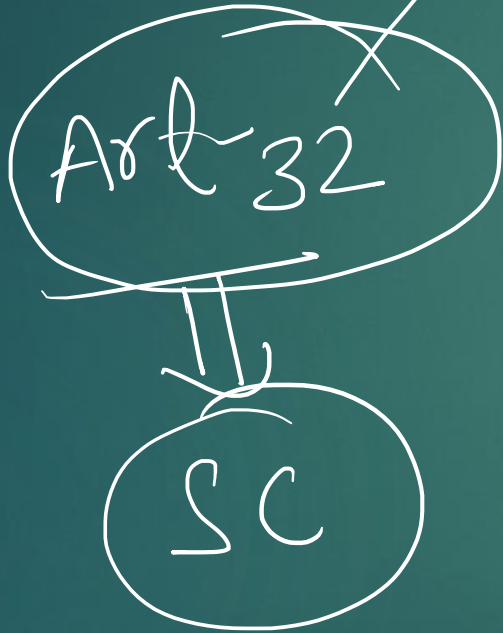
3. They are justiciable, allowing persons to move the courts for their enforcement, if and when they are violated.

4. They are defended and guaranteed by the Supreme Court.

3. वे Justiciable हैं, व्यक्तियों को उनके प्रवर्तन के लिए अदालतों में स्थानांतरित करने की अनुमति है, अगर और जब वे उल्लंघन कर रहे हैं ।

4. सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनका बचाव और गारंटी दी जाती है ।

~~RR~~
FR-Violation
उल्लंघन



5. They can be suspended during the operation of a National Emergency except the rights guaranteed by Articles 20 and 21.

5. वे अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटी अधिकारों को छोड़कर एक राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है।

(Art-352)

6. Their application to the members of armed forces, para-military forces, police forces, intelligence agencies and analogous services can be restricted or abrogated by the Parliament (Article 33).

6. सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अनुरूप सेवाओं के सदस्यों को उनके आवेदन को संसद (अनुच्छेद 33) द्वारा प्रतिबंधित या निरस्त किया जा सकता है ।

7. Fundamental rights can be restricted while martial law is in force in any area.

Martial law means 'military rule' imposed under abnormal circumstances to restore order (Article 34).

Const. ने Define X

7. मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है जब मार्शल लॉ किसी भी क्षेत्र में लागू है।

मार्शल लॉ का मतलब है 'सैन्य शासन' (अनुच्छेद 34)।